भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1998

जिसका उत्तर मंगलवार), दिनांक 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946(शक(को दिया जाना है (

वर्ष 2047 तक विकसित भारत

1998. श्रीमती संगीता यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों के संभावित योगदान के आधार पर उनका मूल्यांकन कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए उपायों और विकास मार्ग को रेखांकित किया गया है। प्रस्तावित विकास उपायों में कृषि विकास और उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता का निर्माण, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, एमएसएमई का समर्थन करना, रोजगारपरक विकास को संभव बनाना, व्यक्तियों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति हासिल करना, निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को संपोषित करना सहित दस प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के इंजन के रूप में और कराधान, वित्तीय क्षेत्र, विनियमों और अन्य क्षेत्रों में सुधारों को समावेशी विकास को बढ़ावा देने के रूप में चिह्नित किया है।

(घ) और (ङ): केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने विकसित भारत की विचारधारा के अनुरूप विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी परिवर्तनों के प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया है।

****